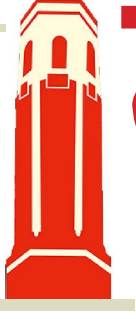


- देहरादून
- वर्ष 32
- अंक 313
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

एक नजर

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर स्कूटी सवार की मौत

देहरादून(संवाददाता)। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर स्कूटी सवार की मौत होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरेली निवासी अभय शर्मा अपनी स्कूटी से डोईवाला से हरिद्वार की तरफ जा रहा था जब वह लालतपड़ के पास पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने उसको अपनी चपेट में ले लिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसको आसपास के लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घर से तीन मोबाइल चोरी

देहरादून(संवाददाता)। चोरों ने घर से तीन मोबाइल चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नई बस्ती रेसकोर्स निवासी अनीता ने नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह घर से बाजार तक गयी थी। जब वह वापस आयी तो उसने देखा कि घर में रखे तीन मोबाइल फोन अपने स्थान से गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शराब के साथ गिरफ्तार

देहरादून(संवाददाता)। पुलिस ने शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रायपुर थाना पुलिस ने एटीएस कालोनी के पास एक व्यक्ति को सदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोड़ी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 55 पच्चे बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम सन्नी पुत्र भगवान दास निवासी खुडबुडा मोहल्ला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

दो दुपहिया वाहन चोरी

देहरादून(संवाददाता)। चोरों ने दो स्थानों से दो दुपहिया वाहन चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार ग्राम माजरी निवासी शेरददीन ने सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी काम से मेदनीपुर गया था तथा उसने अपनी मोटरसाईकिल मोबाइल की दुकान के बाहर खड़ी कर दी थी। जब वह थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसकी मोटरसाईकिल अपने स्थान से गायब थी। जमनीपुर निवासी सोहिल ने विकासनगर कोतवाली में हर्बटपुर से अपनी मोटरसाईकिल चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों मुकदमों दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

जैन मंदिर में चोरों का धावा, लाखों की मूर्तियां और सामान साफ

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। मंगलौर स्थित जैन मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने यहां दान पात्र से रकम चोरी की इसके साथ ही मूर्तियां आदि सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरी में लगभग 40 से 50 लाख का सामान चला गया है।

जानकारी के अनुसार मंगलौर कस्बे में जैन मंदिर के पुजारी जब आज सुबह मंदिर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मामले की सूचना तत्काल उन्होंने मन्दिर समिति के पदाधिकारियों को दी और पुलिस को भी अवगत करवाया गया। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते मन्दिर के अंदर दाखिल हुए और श्री दिगंबर जैन मंदिर का ताला तोड़कर मूर्तियां, चक्र, छतरी, थाल और अन्य कीमती धार्मिक किताबें



अपने साथ ले गए। इसके साथ ही चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ में ले गए। मामले की जानकारी पाकर एसपी देहात शंखर चंद्र सुयाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि फिलहाल मंदिर समिति की ओर से कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। वहीं चर्चा है कि चोरी हुए सामान की कीमत

चालीस से पचास लाख करीब है। बहरहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है।

बता दें कि उत्तराखण्ड के मन्दिरों में लाखों करोड़ों की चोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी राज्य के मन्दिरों में चोरी की कई घटनाएँ हो चुकी हैं। राजधानी देहरादून के राजपुर

रोड स्थित साई मन्दिर में कुछ वर्ष पूर्व चोरों ने करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला था। जिसमें चोर मन्दिर से सोने चांदी के सामान के साथ ही मूर्तियां भी साथ ले गये थे। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया था तो उसमें अंतरराज्यीय चोरों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था।

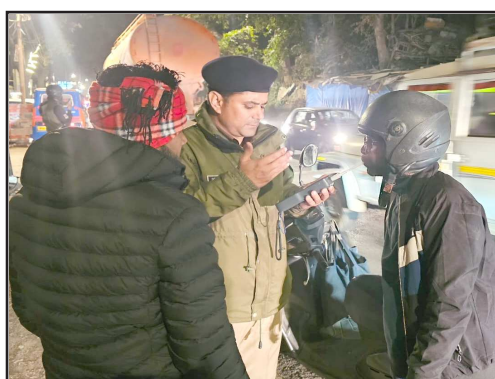
इंकन ड्राइव/रैश ड्राइविंग में किए 18 वाहन सीज, 14 व्यक्ति गिरफ्तार

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने व रैश ड्राइविंग में 18 वाहन सीज कर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

आज यहां आयुष अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार जनपद में शराब पीकर तथा तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल तथा क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर के निर्देशन में

उपरोक्त अभियान के अंतर्गत रात्रि में मुनि की रेती क्षेत्र में चेकिंग टीमों का प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती द्वारा थाना गठन किया गया। पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र



में मधुबन तिराहा, शिवानंद गेट तथा तपोवन तिराहा चेकिंग प्वाइंटों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत इंकन ड्राइव तथा तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने वाले 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर

चार पहिया/दुपहिया वाहनों को सीज किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर 04 वाहन सीज किए गए 15 वाहनों से 8 हजार रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया। चेकिंग अभियान में योगेश चंद्र पाण्डेय, सचिन पुंडीर, जितेंद्र कुमार, नन्द किशोर, प्रदीप रावत, किशन देवराणी, मनोज ममगाई, आशीष शर्मा, दीपक रावत तथा थाना मुनि की रेती के कर्मचारी सम्मिलित रहे। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

दून वैली मेल

संपादकीय

अर्थव्यवस्था का सच

आपने इस कहावत को अनेक बार सुना होगा न खाता न बही जो हम कहें वही सही। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की 10 साल के कार्यकाल को देश में अब तक बनी तमाम गैर भाजपा सरकारों से बेहतरीन बताते हुए चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि लेखा पट्टी का काम करने वाले चाहे तो उनके काम की समीक्षा कांग्रेस, कम्युनिस्ट और परिवारवादियों तथा मिली जुली सरकारों के कामकाज के निर्धारित पैरामीटर को सामने रखकर कर सकते हैं शायद प्रधानमंत्री को यह आभास नहीं रहा होगा कि आज के इस डिजिटल युग में हर किसी को कोई भी जानकारी सहज उपलब्ध है अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी बात पर हर कोई वैसा ही भरोसा कर लेता जैसे अच्छे दिनों के वादों पर कर लिया था। या काला धन वापस लाने और गरीबों के खातों में 15-15 लाख डालने में किया गया था। आज वर्तमान समय में देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है वह 658 मिलियन डॉलर है तथा विदेशी कर्ज 686 मिलियन डॉलर है। जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसके आधार पर सरकार अपना बजट बनती है, से भी अधिक है। देश के इसी आर्थिक हालात को देखकर विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजाया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विदेशी कर्ज में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है आरबीआई द्वारा सरकार को बार-बार चेतावनियां देने की कोशिश की जाती रही हैं जिन्हें नजर अंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 64 के आसपास थी तब वह इसे राष्ट्रीय असम्मान का प्रतीक बताकर मनमोहन सरकार की आलोचना करते थे लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85.20 हो गई है तो उन्हें रुपए की कीमत का अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ रहा है तथा जवाब देही से बचने के लिए विश्व के कुछ राष्ट्रों के बीच सीधे युद्ध व आर्थिक मंदी का हवाला देकर बचाव का रास्ता ढूंढा जा रहा है। भाजपा की जब 2014 में सरकार बनी थी तब देश के किसानों पर 13 लाख करोड़ के आसपास बैंक कर्ज था जो अब 50 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। 2022 तक किसानों की आय दो गुना हो जानी चाहिए थी लेकिन आज देश का हर किसान 75000 के कर्ज में है आज देश के किसानों की औसत मासिक आय 12 से 18 हजार रुपए पर अटकी हुई है जबकि विश्व के किसानों की आय 94 हजार रुपए है। नोटबंदी के बाद देश के एमएसएमई सेक्टर का धराशाई होना और देश में अरबपतियों की संख्या का बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि कॉर्पोरेट के हाथों में देश के संसाधन और संपदा को खुले हाथों से दिया जा रहा है। देश में बेरोजगारी की स्थिति सारी सीमाओं को पार कर चुकी है 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की जो बात कही गई थी वह अब शगुफा साबित हो चुकी है किंतु इसके बाद भी प्रधानमंत्री इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल में विकास का नया इतिहास लिखा गया है 25 करोड़ लोगों को गरीबों की रेखा से बाहर लाया गया है। जिस देश के 80 करोड़ लोग सरकारी 5 किलो राशन पर आश्रित होकर रह गए हो और नौकरियों (सार्वजनिक क्षेत्र) 6.5 फीसदी की कमी आ गई हो किसान कर्ज में डूबे हो और रुपया रसातल में जा पहुंचा हो फिर इतना बड़ा झूठ किसके लिए। शायद सच को देखना भी सत्ता के वश की बात नहीं है। सच को कोई भी बदल तो नहीं सकता है। देश के आम आदमी किसान मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का हाल क्या है? यह अब किसी से छुपा नहीं है न ही अब वह किसी तरह से छुपाया जा सकता है।

अभय शर्मा उर्फ हनी हत्याकांड में फरार चल रहा हत्यारा गिरफ्तार मुख्य आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस

हमारे संवाददाता
हरिद्वार। अभय शर्मा उर्फ हनी हत्याकांड में फरार चल रहे दूसरे हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुख्य हत्यारे को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जानकारी के अनुसार बीते 24 नवम्बर को थाना श्यामपुर क्षेत्रांतर्गत रवासन नदी के किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था।

श्यामपुर पुलिस की दिन रात की मेहनत से शव की पहचान पश्चिमी दिल्ली निवासी अभय शर्मा उर्फ हनी के



रूप में हुई थी। जिस पर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी से जोड़ते हुए हत्या की वजह का पता लगाकर हत्या के मुख्य आरोपी नीरज शुक्ला पुत्र त्रिभुवन शुक्ला निवासी विकासपुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जबकि हत्याकांड में फरार आरोपी की तलाश हेतु की जा रही मेहनत के परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा आज घटना में फरार आरोपी नागेन्द्र पुत्र सिंहराज निवासी हरियाण को लोहे का पुल नहर पट्टी के पास कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से दबोचा गया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

भीमताल बस हादसा: परिवहन निगम की मंडलीय प्रबंधक संचालन अधिकारी निलंबित

हमारे संवाददाता

नैनीताल। भीमताल में बीते रोज उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में उत्तराखंड परिवहन निगम कुमाऊं मंडल की मंडलीय प्रबंधक संचालन पूजा जोशी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार जोशी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरएम पूजा जोशी ने उच्च अधिकारियों के फोन भी रिसीव नहीं किए साथ ही वह तत्काल घटना स्थल पर भी नहीं पहुंची। विदित हो कि बीते रोज भीमताल-हल्द्वानी मार्ग पर आमडाली के पास एक कार को बचाने के प्रयास में रोडवेज



की बस पैराफिट तोड़ते हुए 150 फीट गहरी खाई में गिर गयी थी। हादसे में दम्पति सहित पांच लोगों की मौत हो गयी थी जबकि चालक-परिचालक सहित

26 यात्री घायल हो गये थे। मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकार ने मंडलीय प्रबंधक संचालन पूजा जोशी को निलंबित कर दिया है।

एसडीसी फाउंडेशन ने जारी की चारधाम यात्रा 2024 पर पाथवेज टू पिलग्रिमेज 192 दिन और 28 हफ्तों का 14 ग्राफ के साथ लेखा जोखा'

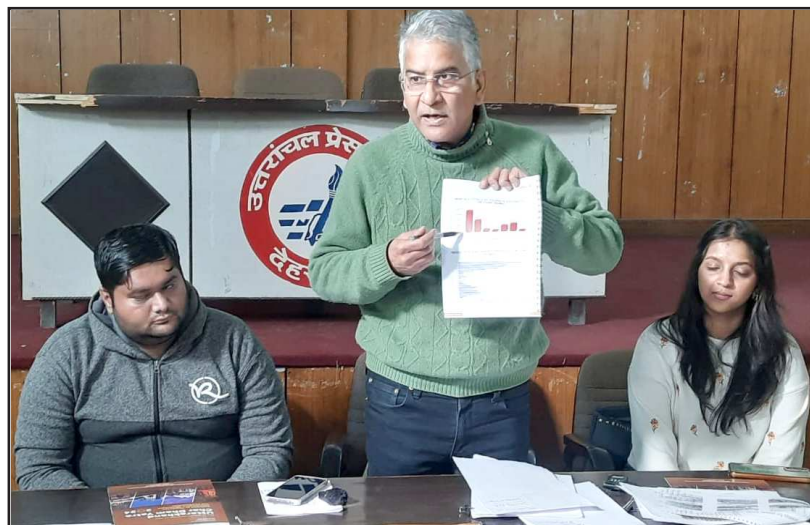
संवाददाता

देहरादून। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज (एसडीसी) फाउंडेशन ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा-2024 पर 'पाथवेज टू पिलग्रिमेज: डेटा इनसाइट्स, चैलेंजेस एंड ऑपॉर्चुनिटीज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

आज यहां उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, शहरीकरण और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने वाली संस्था, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज (एसडीसी) फाउंडेशन ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा-2024 पर 'पाथवेज टू पिलग्रिमेज: डेटा इनसाइट्स, चैलेंजेस एंड ऑपॉर्चुनिटीज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गयी। रिपोर्ट जारी करते हुए एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा की 66 पन्ने की इस विस्तृत रिपोर्ट में यात्रा की 10 प्रमुख बातों को रेखांकित करने के साथ ही यात्रा के संबंध में कई नये

आकलन भी किये गये हैं। रिपोर्ट में 28 हफ्ते और 192 दिन तक हर धाम में हर दिन पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 14 ग्राफ के माध्यम से 10 प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। मीडिया डॉक्यूमेंटेशन च्के एनालिसिस और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को सरल बनाने के एक स्पेशल फीचर के साथ कई और सुझाव भी इस रिपोर्ट में दिये गये हैं। रिपोर्ट में आंकड़ों के आधार पर 10 मुख्य आकलन प्रस्तुत किये गये हैं। मसलन 41 प्रतिशत च्थीर्थ यात्रियों ने पहले घंटे महीने या 30 दिन में, यानी 10 मई से 8 जून तक चार धामों की यात्रा की और बाकि 59 प्रतिशत तीर्थ यात्रियों ने अगले पांच महीनों में चार धामों की यात्रा की। विवरण के लिए 31वें दिन से 60 वें दिन तक 22 प्रतिशत, 61वें दिन से 90वें दिन तक 5 प्रतिशत, 91वें दिन से 120वें दिन तक 3 प्रतिशत, 121वें दिन से 150 वें दिन तक

12 प्रतिशत, 151वें दिन से 180वें दिन तक 15 प्रतिशत 181वें दिन से यात्रा की समाप्ति, यानी 192वें दिन तक 3 प्रतिशत यात्री चारधाम पहुंचे। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण आकलन यह है कि तीर्थयात्रा का दूसरा हफ्ता, यानी 17 मई से 23 मई, सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाला रहा। 28 हफ्ते घुली यात्रा में इस एक हफ्ते में ही 5,63,292 यात्रियों के साथ यात्रा के कुल 12 प्रतिशत तीर्थयात्री घुमने पर आये। अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। 31 जुलाई की आपदा के कारण 1 से 10 अगस्त तक एक भी यात्री केदारनाथ नहीं पहुंचा। 11 से 20 अगस्त तक 1,148 तीर्थयात्री, 21 से 31 अगस्त तक 6,270 तीर्थयात्री ही केदारनाथ पहुंच पाये। अगस्त के पूरे महीने में सिर्फ 7,418 तीर्थयात्री केदारनाथ आये। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में यात्रा का दायरा बढ़ा है। यह विस्तार कई चुनौतियों के साथ हुआ है। रिपोर्ट में



चारधाम यात्रा 2024 के प्रबंधन, स्थिरता और प्रभाव के साथ ही यात्रा में भीड़भाड़, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और पर्यावरणीय गिरावट को भी इंगित किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार का ध्यान रिकॉर्ड तोड़ने वाली संख्या का जश्न मनाने से हटकर यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि यात्रा का प्रबंधन, तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और इन पवित्र स्थलों पर निर्भर समुदायों का कल्याण कैसे संभव हो सकता है।

कफ सिरप लेने से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण

खांसी, गले में दुखन और जलन के साथ सांस लेने में तकलीफ होना कोरोना संक्रमण के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं। इस तरह की दिक्कत होने पर लोग अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का सेवन कर लेते हैं। इस बात में कोई शक भी नहीं है कि कफ सिरप लेने से इन दिक्कतों में आराम महसूस होता है। लेकिन यह बात तब फिट बैठती है, जब आपको सामान्य कारणों या बदलते मौसम के कारण गले से जुड़ी इस तरह की समस्याएं हो रही हों।

क्यों नहीं लेनी है कफ सिरप?

हम सभी जानते हैं कि इटली और अमेरिका में कोरोना वायरस ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। इन देशों में कोरोना के संक्रमण को अधिक घातक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये विकसित देश हैं और इनके पास अपने नागरिकों को देने के लिए सभी जरूरी सुख-सुविधाएं हैं।

लेकिन फिर भी ये देश इस संक्रमण पर काबू नहीं कर पाए।

साथ ही कोरोना हम सभी के लिए एकदम नया वायरस था और इसके बारे में शुरुआत में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि आज भी कोरोना पर लगातार रिसर्च हो रही है। हाल ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात पर परीक्षण किया कि यदि कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति गले के दर्द और खांसी से राहत पाने के लिए कफ सिरप का उपयोग करता है तो उसकी सेहत पर कैसा असर पड़ता है।

इस शोध को कोरोना संक्रमित अफ्रीकी बंदरों पर किया गया। क्योंकि इन बंदरों पर किसी भी दवाई का असर ठीक उसी तरह होता है, जैसे इंसान पर किसी दवा का असर होता है। शोध टीम से जुड़े प्रोफेसर ब्रिगन का कहना है कि जब हमें शोध में इस तरह के परिणाम देखने को

मिले कि बंदरों में कफ सिरप के उपयोग से कोरोना वायरस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तब हमें लगा कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी होनी



चाहिए कि कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का सेवन नहीं करना है।

कफ सिरप से क्यों बढ़ रहा कोरोना?

कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा अगर ऐसी कफ सिरप का सेवन कर लिया जाता है, जिसे बनाने में डेक्सट्रोमेथॉफेन ड्रग का उपयोग किया गया हो तो यह दवाई मरीज

की समस्या कम करने की जगह बढ़ा सकती है। -ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेक्सट्रोमेथॉफेन ड्रग हमारे शरीर में पहुंचने के बाद जिस तरह से रिएक्ट करती है और काम करती है, वह सब कोरोना को रिएलेशन में मददगार होता है। यानी इस ड्रग की मदद से कोरोना वायरस को अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है।

शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद अगर मरीज इस तरह की कफ सिरप का उपयोग करते हैं तो यह बात तो तय है कि उनके शरीर में कोरोना वायरस में वृद्धि होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर मरीज पर वायरस की संख्या में वृद्धि का एक जैसा असर दिखाई दे।

डेक्सट्रोमेथॉफेन ड्रग क्या है?

डेक्सट्रोमेथॉफेन ड्रग एक ऐसा कम्पोजिशन है, जिसका सेवन करने पर

हमें खांसी की समस्या में तेजी से आराम मिलता है। यही वजह है कि आमतौर पर सभी कफ सिरप बनाने में इस ड्रग का उपयोग किया जाता है।

शोधकर्ताओं की यह टीम कोरोना के दौरान मरीज में दिख रहे लक्षणों के आधार पर इस बात की जांच कर रही है कि जब कोरोना से पहले इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है, उन दवाओं का असर कोरोना के मरीजों पर किस तरह हो रहा है।

टीम का कहना है कि ऐसी कई ड्रग्स का कलेक्शन तैयार किया गया है, जो वायरस की वृद्धि को रोकने का काम करती हैं। अब कोरोना संक्रमित जानवरों पर उन ड्रग्स का ट्रायल किया जा रहा है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ये दवाएं शरीर में जाने के बाद किस तरह से रिएक्ट करती हैं।

गर्मी में घमौरियों से हो रहे हैं परेशान 5 मिनट में इन 5 चीजों से करें इलाज

गर्मी के मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को घमौरियां बहुत ही कष्ट पहुंचाती हैं। इस मौसम में न सिर्फ कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं बल्कि शरीर में घमौरियों की वजह से तेज खुजली भी होती है। घमौरी से शरीर खुजलाने के कारण जलन और इचिंग भी बढ़ जाती है। इससे शरीर पर रैशज भी हो जाते हैं। त्वचा संबंधी यह दिक्कत यूं तो बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन सभी को परेशान कर देती है। आप चाहें तो इसे घर पर ही कुछ आसान टिप्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो घरेलू नुस्खे।



क्या होती है घमौरी- चिलचिलाती हुई गर्मी में जब पसीने की वजह से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, तो शरीर पर लाल रंग के छोटे-छोटे दागें निकल आते हैं। इनमें बेहद तेज खुजली होती है और जलन महसूस होती है। इन्हीं दागों को घमौरियां कहते हैं। यह अक्सर पीठ, छाती, बगल व कमर के आसपास होती है। यह कई बार अपने आप ठीक हो जाती है मगर कई

बार इन्हें कुछ उपायों से ठीक करना पड़ता है।

मुल्लानी मिट्टी

मुल्लानी मिट्टी का इस्तेमाल लंबे समय से घमौरियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह बंद पोर्स को खोलती है और स्किन को रिफ्रेश करती है। इसे लगाने के लिए इसको गुलाब जल के साथ मिक्स करें। फिर प्रभावित जगह पर लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। गर्मियों में इसे रोज लगाएं और जब फर्क दिखाई पड़ने लगे तो एक दिन छोड़ कर लगाना शुरू करें। जल्द ही असर नजर आएगा।

खीरा- गर्मी की वजह से स्किन पर होने वाली खुजली को खीरा लगाकर आसानी से ठीक किया जा सकता है। यह त्वचा को तुरंत निखारता है और ठंडक पहुंचाता है। इसके लिए आधा खीरा लेकर उसे छीलें और पतले स्लाइस काट लें। इन्हें कुछ मिनटों के लिए फ्रिज में ठंडा करें और फिर उन्हें घमौरियों पर लगाएं।

बेकिंग सोडा- बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह गर्मी और पसीने की वजह से शरीर पर पैदा होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करता है। 2 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 कटोरी पानी में मिलाकर शरीर के प्रभावित क्षेत्र को साफ करें। रोजाना दिन में 2 बार ऐसा करने से लाभ मिलता है।

एलोवेरा जेल- एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो गर्मी के कारण होने वाली घमौरियों से राहत दिलाते हैं। यह खुजली के साथ लाल रंग के रैशज को भी दूर करता है। अगर आपको घमौरियों से बचना है तो ताजा एलोवेरा जेल लगाएं। इसे कम से कम दिन में दो बार जरूर लगाएं।

बर्फ-

बर्फ की ठंडक त्वचा की गर्मी और खुजली को शांत करती है। एक कॉटन के कपड़े में 2-3 आइस क्यूब लेकर उसे घमौरी वाली जगह पर लगाएं। आप चाहें तो पानी में बर्फ डालकर उसे पिघलने दें और फिर उसमें कपड़ा भिगोकर प्रभावित क्षेत्र को सिकाई कर सकते हैं। बर्फ लगाने से खुजली में राहत मिलती है।

कितनी भी गर्मी हो, फ्रिज में नहीं रखने चाहिए ये फल और सब्जियां

किसी भी फल और सब्जी को जब भी लंबे समय तक स्टोर करने की बात आती है तो हम पूरी तरह अपने फ्रिज पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फल और सब्जियां फ्रिज में रखने पर ज्यादा दिन सही रहने की जगह जल्दी खराब हो जाते हैं? आइए, आज इन्हीं फल और सब्जियों के बारे में जानते हैं...

कच्ची प्याज फ्रिज में नहीं रखते हैं

प्याज को स्टोर करना है तो इसके लिए रूम टेम्प्रेचर बेस्ट होता है। बस इस पर सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़नी चाहिए। फ्रिज में स्टोर करने पर प्याज की लाइफ बढ़ने की जगह कम हो जाती है। क्योंकि प्याज में खुद बहुत मॉइश्चर होता है और फ्रिज की ठंडक में यह जल्दी गल जाती है।

अगर आपको छिली हुई और कच्ची प्याज स्टोर करनी है तो इसके लिए किसी

एयर टाइट कंटेनर में प्याज को रखें और वेजिटेबल बॉक्स के अंदर इसे फ्रिज में रखें।

कच्चा आलू फ्रिज में नहीं रखते

आलू सब्जियों का राजा है और फिर इसे लंबे समय तक ठंडे और छायादार स्थान पर आराम से स्टोर भी किया जा सकता है। क्योंकि यह स्टार्च से भरपूर होता है इसलिए छायादार और मद्धम प्राकृतिक रोशनी में रखा हुआ आलू लंबे समय तक सही रहता है।

लेकिन आप कच्चे आलू को फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इनके अंदर का स्टार्च फ्रिज के बहुत अधिक ठंडे तापमान में रासायनिक रूप से टूटने लगता है। इससे इस स्टार्च का स्वाद बदल जाता है और फिर आलू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं।

खरबूजा फ्रिज में नहीं रखते हैं

खरबूजे को फ्रिज में रखने पर सबसे



पहली दिक्कत तो यह होती है कि इसके साथ में और जितनी भी चीजें फ्रिज में रखी होंगी, उन सभी में खरबूजे की स्पेल बस जाती है। साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स का असर कम हो जाता है। ऐसे में इसे खाने का पूरा लाभ शरीर को नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह कि फ्रिज में अधिक दिन तक रखने के बाद खरबूजे का नैचरल टेस्ट गायब हो जाता है। उसमें नैचरल और फ्रेश आरामा नहीं रह जाता है। इसलिए खरबूजे को रूम सामान्य तापमान पर कुछ

दर के लिए पानी में भिगोकर रखना चाहिए। **लहसुन फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं** -कच्चा लहसुन अगर आपको लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो इसे कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं। बल्कि ऐसी जगह पर स्टोरी करते हैं जहां बिल्कुल नमी ना हो और हल्की-हल्की प्राकृतिक रोशनी भी आ रही हो।

फ्रिज में लहसुन रखने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है। साथ ही इसकी अपनी स्पेल फ्रिज में रखी बाकी चीजों में भी आने लगती है। यानी अगर आप फ्रिज में लहसुन के साथ रखा गया दूध पिपिंगे तो आपको दूध में से भी लहसुन की ही खुशबू आएगी।

केले को फ्रिज में नहीं रखते

केले को भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि केले का ऊपरी छिलका काफी नरम और नमी से भरपूर होता है।

दही भी कोई दिक्कत नहीं करता है। वैज्ञानिक रूप से तो दही के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह आयुर्वेदिक कांसेप्ट है की हमें ठंडा और गर्म खाना मिक्स नहीं करना चाहिए। इससे आपको गले में परेशानी और सूजन हो सकती है।

कब और कैसे खाएं दही?

दही सबसे अधिक फायदेमंद नाश्ते में खाने से होता है। दही में चीनी मिलाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। पेट की परेशानी को दूर करने के लिए दही से बानी लस्सी या छाछ भी सेहत के लिए अच्छी होती है। रात को दही खाने से इसे पचाने में मुश्किल हो सकती है। इस तरह के भोजन को पचाने के लिए एनर्जी बर्न करनी की जरूरत पड़ती है। खाने के बाद तुरंत सोने से पाचन तंत्र कमजोर होता है। दही सूजन को बढ़ाता है, इसलिए शरीर में सूजन हो तो इसे न खाएं।

गलत समय पर दही कर सकते हैं बड़ी परेशानी- रात में दही खाने से खांसी-जुखाम, जोड़ों के दर्द की परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हो सके तो रात के समय दही खाने से परहेज करना ही बेहतर होता है। दही को रात के साथ-साथ बसंत में भी नहीं खाना चाहिए।

यह केले को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। यदि आप केले को फ्रिज में रखेंगे तो इसका छिलका गल जाएगा।

छिलका गलने से केले की लाइफ बढ़ने की जगह घट जाती है। साथ ही फ्रिज में रखे गए केले का टेस्ट बदल जाता है और यह खाने में फ्रेश केले की तरह स्वादिष्ट नहीं लगता है।

सेब को फ्रिज में रखने से बचें

आपको जानकर हैरानी होगी कि सेब को अगर कमरे के सामान्य तापमान पर और सही तरीके से रखा जाए तो इन्हें करीब दो सप्ताह तक स्टोर किया जा सकता है।

फ्रिज में रखने से सेब का स्वाद और इसकी क्रिस्पिनेस कम होती है। अगर आप सेब का नैचरल टेस्ट इंजाय करना चाहते हैं तो इन्हें क्लीन करके अपनी डायनिंग टेबल पर फ्रूट बकेट में रखें ना कि फ्रिज में।

श्याम बेनेगल का जाना नये सिनेमा का अंत

ललित गर्ग

बालीवुड में समानांतर सिनेमा के जनक, 'मंथन' से लेकर 'वेलडन अब्बा' तक जिनके फिल्मी सफर को एक युग कहा जा सकता है, बेहद कलात्मक, बेहद संजीदा, बेहद संवेदनशील, ऐसे बेमिसाल फिल्मकार श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में जाना अत्यंत दुखद ही नहीं है, एक सार्थक भारतीय सिनेमा एवं गौरवशाली टेलीविजन युग का अंत है। दादा साहब फाल्के के अलावा सात राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बेनेगल ने हिंदी सिनेमा को नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, अनंत नगा जैसे प्रख्यात कलाकार दिए। उनकी फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा का एक नया और अविस्मरणीय दौर शुरू हुआ, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। पिता के कैमरे से 12 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाने वाले बेनेगल ने उस समय अहसास कराया कि भारतीय सिनेमा में एक विराट प्रतिभा मोर्चा संभाल चुकी है, जिसके काम की गुंज उनकी जीवन में ही नहीं, बल्कि भविष्य में लम्बे समय तक देश और दुनिया को सुनाई देगी। जब-जब हमने बहुत ठहरकर, बहुत संजीदगी के साथ उनके काम को देखा तो अनायास ही हमें महसूस हुआ कि वे अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए थे, अद्भुत, यादगार एवं विलक्षण। सिनेमा दर्शकों का ऐसे महान् फिल्मकार की फिल्मों से अनभिन्न रहना इस संसार में रहते हुए भी सूर्य, चन्द्रमा एवं तारों को न देखने जैसा है।

श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसम्बर 1934 को हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद की ओसमानिया यूनिवर्सिटी से इकोनोमिक्स में एमए करने के बाद बेनेगल ने आगे जाकर हैदराबाद फिल्म सोसायटी की स्थापना की। उनका संबंध कोंकणी बोलने वाले चित्रपुर सारस्वत परिवार से था। उनका असली नाम श्याम सुंदर बेनेगल था। श्याम

बेनेगल की शादी नीरा बेनेगल से हुई थी और उनकी एक बेटी पिया बेनेगल है, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए भी काम किया है। श्याम ने बचपन में ही अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी. बेनेगल के कैमरे से पहली फिल्म शूट की थी। 1962 में उन्होंने पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'घर बैठा गंगा' बनाई, जो गुजराती में थी। बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी सफल फिल्मों में मंथन, जुबैदा और सरदारी बेगम शामिल हैं। जिनमें जीवन के कठोर यथार्थ को बेनेगल ने सिनेमा-शिल्प में, महीन अर्थवत्ता के साथ नाटकीयता के धनीभूत आशयों में अभिव्यक्ति दी, प्रस्तुति दी है। उनकी फिल्मों में एक ऐसी सार्वजनिकता है, जो धनी-निर्धन, शिक्षित-अशिक्षित, देशी-विदेशी सभी को बहुत भीतर तक स्पर्श करती रही है।

श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म 'मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन' थी, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था। इस फिल्म ने भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में भी सुर्खियां बटोरीं। यह फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान पर आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ने बांग्लादेश में 2024 में तख्तापलट करवा दिया था और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। यह फिल्म दिखाती है कि मुजीबुर्रहमान के राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई थी, उन्होंने किस तरह बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए काम किया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम ने मिलकर बनाया था। यह फिल्म जहां एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रस्तुति दी, वहीं दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को भी गहराई से उजागर किया। इस फिल्म को

बंगाली के साथ-साथ हिन्दी भाषा में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म का एलान करते हुए बेनेगल ने बताया था कि शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके लिए एक कठिन काम रहा है। उन्होंने कहा था, यह फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। मुजीब के किरदार को बेबाकी से पेश किया है, वे भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे। उनकी यह फिल्म ही नहीं, बल्कि हर फिल्म ने एक इतिहास निर्मित किया। क्योंकि यह उनकी ही प्रतिभा थी कि वे लगातार काम करने की रणनीतियों में बदलाव लाते रहे और फिल्म-निर्माण को एक विराट फलक तक ले जाते रहे। भारतीय सिनेमा के लगभग सौ साला इतिहास में बेनेगल एक बड़े बटवृक्ष की भांति दिखाई देते हैं।

भारतीय सिनेमा को विश्व में नई और अद्वितीय पहचान दिलाने में बेनेगल का अविस्मरणीय योगदान था। बेनेगल की पहली चार फीचर फिल्मों- अंकुर (1973), निशांत (1975), मंथन (1976) और भूमिका (1977)- ने उन्हें उस दौर की नई लहर फिल्म आंदोलन का अग्रणी बना दिया। बेनेगल की मुस्लिम महिला पर आधारित फिल्में मम्मो (1994), सरदारी बेगम (1996) और जुबैदा (2001) सभी ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 1959 में, उन्होंने मुंबई स्थित विज्ञान एजेंसी लिंटास एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइट के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ वे धीरे-धीरे क्रिएटिव हेड बन गए। 1963 में एक अन्य विज्ञापन एजेंसी के साथ कुछ समय तक काम किया।

इन वर्षों के दौरान, उन्होंने 900 से अधिक प्रायोजित वृत्तचित्र और विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन किया। 1966 और 1973 के बीच बेनेगल ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में पढ़ाया और दो बार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में

कार्य किया। उनके शुरुआती वृत्तचित्रों में से एक 'ए चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट्स' (1967) ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। कुल मिलाकर, उन्होंने 70 से अधिक वृत्तचित्र और लघु फिल्में बनाई हैं। बेनेगल ने 1992 में धर्मवीर भारती के एक उपन्यास पर आधारित सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म बनाई, जिसने 1993 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।

1996 में उन्होंने फतिमा मीर की 'द अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा' पर आधारित पुस्तक द मेकिंग ऑफ महात्मा पर आधारित एक और फिल्म बनाई। उनके जीवनी सामग्री की ओर इस मोड़ के परिणामस्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस: द फॉरगॉटन हीरो, उनकी 2005 में अंग्रेजी भाषा की फिल्म बनी। उन्होंने समर (1999) में बनी फिल्म में भारतीय जाति व्यवस्था की आलोचना की, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बेनेगल की फिल्म मंडी (1983), राजनीति और वेश्यावृत्ति के बारे में एक व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी थी, जिसमें शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल ने अभिनय किया था। बाद में, 1960 के दशक की शुरुआत में गोवा में पुर्तगालियों के अंतिम दिनों पर आधारित अपनी कहानी पर काम करते हुए, श्याम ने त्रिकाल (1985) में मानवीय रिश्तों की खोज की। इन फिल्मों की सफलता के बाद, बेनेगल को स्टार शशि कपूर का समर्थन मिला, जिनके लिए उन्होंने जुनून (1978) और कलयुग (1981) बनाई। पहली फिल्म 1857 के भारतीय विद्रोह के अशांत काल के बीच की एक अंतरजातीय प्रेम कहानी थी, जबकि दूसरी महाभारत पर आधारित थी और यह बड़ी हिट नहीं थी, हालांकि दोनों ने क्रमशः 1980 और 1982 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते। हजारों अविस्मरणीय किरदार और जिंदगी और दो बार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में

फिल्में भारतीय सिनेमा की एक अमूल्य धरोहर हैं।

एक समय ऐसा आया जब बेनेगल की फिल्मों को उचित रिलीज नहीं मिली। इसके चलते हुए उन्होंने टीवी की ओर रुख किया जहां उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए यात्रा (1986) जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया और भारतीय टेलीविजन पर किए गए सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित 53-एपिसोड का टेलीविजन धारावाहिक 'भारत एक खोज' (1988) का निर्देशन किया। इसी तरह टीवी सीरीयल 'संविधान', 'कहता है जोकर' एवं 'कथा सागर' का निर्देशन भी किया। इससे उन्हें एक अतिरिक्त लाभ हुआ, क्योंकि वे 1980 के दशक के अंत में धन की कमी के कारण नया सिनेमा आंदोलन के पतन से बचने में कामयाब रहे, जिसके साथ कई नव-यथार्थवादी फिल्म का निर्माता खो गया। बेनेगल ने अगले दो दशकों तक फिल्में बनाना जारी रखा।

श्याम बेनेगल की फिल्म-प्रतिभा हमें चौंकाती रही है, रोमांचित करती रही है, उकसाती रही है, क्योंकि उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे आम लोगों के जीवन की सच्चाई और उनके संघर्षों को प्रामाणिकता एवं जीवंतता के साथ प्रस्तुत करते रहे हैं। भारतीय जिंदगी के रंग बेशुमार हैं, कला-संस्कृति की अविस्मरणीय धाराएं हैं, अनूठा एवं बेजोड़ इतिहास और उसकी कहानियां भी अनंत-अथाह। बेनेगल का फिल्मी-युग भारत की खिड़की से विश्व को देखने एवं विश्व को भारत दिखाने की पहल का एक स्वर्णिम युग है। भारतीय सिनेमा दिग्दर्शन के इस विशिष्ट हस्ताक्षर श्याम बेनेगल के निधन से निश्चित ही एक सर्जनशील कलासाधक एवं सच्चाई को रूपहले पर्दे पर उतारने वाले सफल एवं सार्थक फिल्मकार का अंत हो गया।

फ्री फिशिंग एक्ट बनाने को लेकर आंदोलन

कुमार कृष्णन

गंगा बेसिन का लगभग 79 फीसदी क्षेत्र भारत में है। बेसिन में 11 राज्य शामिल हैं - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। गंगा बेसिन से जुड़े सवाल को लेकर गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से बिहार के मुजफ्फरपुर के चंद्रशेखर भवन, मिठनपुरा, में गंगा बेसिन रू समस्याएं एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय विमर्श में जुटे देश के आठ राज्यों और नेपाल के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर गंगा के सवाल पर देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प के तहत गंगा मुक्ति आंदोलन के बैनर तले अपने साथी संगठनों जल श्रमिक संघ, बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी जल श्रमिक संघ के साथ मिलकर भागलपुर समाहरणालय पर अपने आंदोलन का शंखनाद किया। इसी भागलपुर जिले में 22 फरवरी 2025 को गंगा मुक्ति आंदोलन के वर्षगांठ पर कागजी टोला कहलगांव, भागलपुर में पुनः देश भर से परिवर्तनवादी जुटेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। इस लिहाज से आंदोलन का शंखनाद दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

एक तो शासन तंत्र पर दबाव बनाने लिए, दूसरे सांगठनिक मजबूती के लिए। जल श्रमिक संघ के प्रदेश संयोजक योगेंद्र

सहनी ने कहा कि वन विभाग बिहार सरकार द्वारा दिए गए निःशुल्क शिकारमाही के अधिकार को शिथिल करना चाहती है पिछले दिनों वन विभाग ने हजारों रुपए का जाल गंगा किनारे से उठा लिया है और कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इसके विरोध में आंदोलन भी हुआ। गंगा मुक्ति आंदोलन वरिष्ठ संगठक उदय का कहना था कि एक दशक के लंबे संघर्ष के जलकर जमींदारी से मुक्ति मिली। संघर्ष के बाद मछुओं को करमुक्त मछली पकड़ने का अधिकार मिला है जिसे सरकार ने निरस्त नहीं किया है। भागलपुर के गंगा नदी में सुल्तानगंज के जहांगीरा (घोरघट पुल) से पीरपैती के हजरत पीरशाह कमाल दरगाह तक बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने अपने ज्ञापांक 2294 धमत्स्य धू पटना दिनांक 11 दिसंबर 1991 द्वारा पारंपरिक मछुओं हेतु शिकारमाही के लिए निःशुल्क घोषित किया है। निःशुल्क शिकारमाही की घोषणा के पूर्व ही पर्यावरण विभाग बिहार पटना द्वारा 22 अगस्त 1990 को सुल्तानगंज से कहलगांव तक विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र घोषित किया जा चुका था सरकार ने निःशुल्क शिकारमाही के अधिकार को किसी भी आदेश से निरस्त नहीं किया है। वन विभाग मौखिक रूप से जबरन कहता है कि उपरोक्त क्षेत्र में मछली

पकड़ना मना है। मछली पकड़ने से रोकने के लिए तरह तरह का बेबुनियाद, झूठ और मनगढ़ंत आरोप मछुओं पर लगाया जाता है हकीकत ये है कि गैर मछुओं और सोसाइटी द्वारा गंगा में अवैध जाल चलाया जाता है और जिंदा धार में बाड़ी बांधा जाता है उसे वन विभाग कुछ नहीं कहता है। सवालिया लहजा में लोगों का कहना है कि वन विभाग नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत और एनटीपीसी पर गंगा को प्रदूषित कर डॉल्फिन मारने पर कोई कारवाई या मुकदमा क्यों नहीं करती? वन विभाग डॉल्फिन पर नगर निगम के कचरे और एनटीपीसी के कचरे से होने वाले नुकसान पर मुंह क्यों खोलता? वन विभाग उम्र पूरा होने या प्रदूषण से मरने वाले सोंस की संख्या सार्वजनिक क्यों नहीं करता? मत्स्य विभाग मछुओं को निःशुल्क शिकारमाही का परिचय पत्र निर्गत करने में आना कानी और टाल मटोल करता है। वन विभाग अवैध रूप से बाड़ी (जो डॉल्फिन के लिए हानिकारक है) बांधने पर कोई कारवाई क्यों नहीं करती? 1993 के पहले गंगा में जमींदारों की पानीदार थे, जो गंगा के मालिक बने हुए थे। सुल्तानगंज से लेकर पीरपैती तक 80 किलोमीटर के क्षेत्र में जलकर जमींदारी थी। यह जमींदारी मुगलकाल से चली आ रही थी। सुल्तानगंज से बरारी के बीच

जलकर गंगा पथ की जमींदारी महाशय घोष की थी। बरारी से लेकी पीरपैती तक मकससपुर की आधी-आधी जमींदारी क्रमशः मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुसर्फहुसैन प्रमाणिक और महाराज घोष की थी। हैरत की बात तो यह थी कि जमींदारी किसी आदमी के नाम पर नहीं बल्कि देवी-देवताओं के नाम पर थी। ये देवता थे श्री श्री भैरवनाथ जी, श्री श्री ठाकुर वासुदेव राय, श्री शिवजी एवं अन्य। कागजी तौर जमींदार की हैसियत केवल सेवायत की रही है। सन 1908 के आसपास दियारे के जमीन का काफ़ी उलट-फेर हुआ। जमींदारों के जमीन पर आये लोगों द्वारा कब्जा किया गया। किसानों में आक्रोश फैला। संघर्ष की चेतना पूरे इलाके में फैलीय जलकर जमींदार इस जागृति से भयभीत हो गये और 1930 के आसपास ट्रस्ट बनाकर देवी-देवताओं के नाम कर दिया। जलकर जमींदारी खत्म करने के लिए 1961 में एक कोशिश की गयीय भागलपुर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने इस जमींदारी को खत्म कर मछली बंदोबस्ती की जवाबदेही सरकार पर डाल दी। मई 1961 में जमींदारों ने उच्च न्यायालय में इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की और अगस्त 1961 में जमींदारों को स्टे ऑर्डर मिल गया। 1964 में उच्च न्यायालय ने जमींदारों के पक्ष में फैसला

सुनाया तथा तर्क दिया कि जलकर की जमींदारी यानी फिशर्रीज राइट मुगल बादशाह ने दी थी और जल-कर के अधिकार का प्रश्न जमीन के प्रश्न से अलग है। क्योंकि जमीन की तरह यह अचल संपत्ति नहीं है। इस कारण यह बिहार भूमिसुधार कानून के अंतर्गत नहीं आता है। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और सिर्फ एक व्यक्ति मुसर्फहुसैन प्रमाणिक को पार्टी बनाया गया। जबकि बड़े जमींदार मुसर्फहुसैन प्रमाणिक को छोड़ दिया गया।

गंगा मुक्ति आंदोलन के अनिल प्रकाश के अनुसार आरंभ में जमींदारों ने इसे मजाक समझा और आंदोलन को कुचलने के लिए कई हथकंडे अपनाये। लेकिन आंदोलनकारी अपने संकल्प "हमला चाहे कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा" पर अडिग रहे और निरंतर आगे रहे। निरंतर संघर्ष का नतीजा यह हुआ 1988 में बिहार विधानसभा में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए जल संसाधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का एक प्रस्ताव लाया गया। परंतु स्थिति यह है कि गंगा की मुख्य धार मुक्त हुई है लेकिन कोल ढाब व अन्य नदी-नालों में अधिकांश की नीलामी जारी है और सारे पर भ्रष्ट अधिकारियों और सत्ता में बैठे राजनेताओं का वर्चस्व है।

छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है व सिर श्रद्धा से झुक जाता है

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तर पर आदि अनादि काल से भारत की अनेक गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं, जिसका बखान उनके प्रकाशोत्सव वर्षगांठ या उस दुखद पल कुर्बानी दिवस के रूप में उसको याद किया जाता है। इसी कड़ी में 26 दिसंबर 2024 को सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है। देश में पहली बार पीएम के ऐलान के बाद ही 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस पूरे देश-विदेश में मनाया जाता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस स्थान पर खड़ा है, जहां साहबजादों ने आखिरी सांस ली। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को एक बयान जारी करके बताया कि भारत के बच्चों की उपलब्धियों और सामर्थ्य को सम्मानित करते हुए आगामी गुरुवार को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के लिए इस साल 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार समारोह में सात श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सात लड़कों और दस लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा। पीएम बाल पुरस्कार इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बजाय 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में बाल पुरस्कार बांटेगीं पीएम इसके बाद भारत मंडपम में बच्चों से मिले चौक छोटे

साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है व सिर श्रद्धा से झुक जाता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साहस को श्रद्धांजलि, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 पर विशेष। साथियों बात अगर हम वीर बाल दिवस के महत्व व परिभाषा संशोधन की करें तो, यह दिवस खालसा के चार साहबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपने आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह उनकी कहानियों को याद करने का भी दिन और यह जानने का भी दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई-खासकर जोरावर और फतेह सिंह की। सरसा नदी के तट पर एक लड़ाई के दौरान दोनों साहबजादों को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उन्हें क्रमशः 8 और 5 साल की उम्र में कथित तौर पर जिंदा दफन कर दिया गया था। बदली परिभाषा, अब, वीर वह है जो अंधेरो को रोशन करे सरकार ने इस बार वीरता की परिभाषा को भी परिमार्जित किया है। इसमें कहा गया है, वीर वह है जो अंधेरो को रोशन करे। इसमें केवल साहस ही नहीं दया, क्रियाशीलता, नवप्रवर्तन के साथ कुछ कर गुजरे बच्चों जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं को शामिल किया गया है, ताकि इससे देश की युवा पीढ़ी और बच्चे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों। सरकार का मकसद इसके जरिये समग्रता के साथ बच्चों की वीरता और कारनामों को पेश करना है। वीर सपूतों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेना आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने व इसी दिन पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण की करें तो, पीएम आह्वान पर 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे साहबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। 26 दिसंबर को 1705 में इन महान सपूतों को धर्म नहीं बदलने पर प्रतिशोध स्वरूप वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस शहादत को नमन करने के लिए इस बार वीर बाल दिवस के मौके पर बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह वह नौनिहाल हैं, जिन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन बाल प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनाएंगे। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए सात श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्रदान करती है। इस बार 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 26 दिसंबर, 2024 को इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगीं। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दिए जाएंगे। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 दिसंबर, 2024 को ही नई दिल्ली के भारत

मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यह दिन युवा दिमागों को पोषित करने, उनकी रचनात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की भविष्यदृष्टि में योगदान के लिए उन्हें प्रेरित करने पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। आयोजन में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 3,500 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भारतीय विरासत को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बच्चे विविध संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व वाले मार्च पास्ट में भी शामिल होंगे। इसके अलावा माई गाँवधमाई भारत पोर्टल पर ऑनलाइन गतिविधियां सहित देश भर के स्कूलों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाने, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाने, निबंध लेखन, कविता और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।

साथियों बात अगर हम वीर बाल दिवस के इतिहास की करें तो, बताते हैं कि मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह व दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं, माता गुजरी, दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों

से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया लेकिन उसने सरहिंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को कैद कर लिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा-धमकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा लेकिन दोनों साहबजादों ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर को अगले दिन ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहां फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा लेकिन छोटे साहबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहबजादों को शहीद कर दिया। यह खबर जैसे ही माता दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साहस को श्रद्धांजलि-वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 पर विशेष, छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है व सिर श्रद्धा से झुक जाता है। साहबजादों बाबा जोरावर सिंह व फतेहसिंह के सम्मान में बाल दिवस के साथ बाल पुरस्कार 26 जनवरी के स्थान पर 26 दिसंबर को देना सराहनीय निर्णय है।

जीवन पर्यंत शिक्षा की अलख जगाते रहे डॉ श्याम सिंह नागियान

इंजीनियर एवं शिक्षा नगरी रुड़की में डॉ श्याम सिंह नागियान एक बड़ा नाम रहा है। भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट श्याम सिंह नागियान ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रुहालकी में बतौर प्रवक्ता अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर वर्षों तक आईआईटी रुड़की से सम्बद्ध आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रहे, जबकि उनकी पत्नी केंद्रीय विद्यालय में बतौर शिक्षिका सेवारत रही। सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षा के प्रति उनकी ललक कम नहीं हुई बल्कि स्कॉलर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना कर उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान अनवरत बांटने का सपना शुरू किया।

वर्तमान में स्कॉलर एकेडमी में हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लेकिन इस शिक्षा के मंदिर का संस्थापक अचानक हम सबके के बीच से चला गया है। आठ दशक से भी ज्यादा जिंदादिली के साथ जिये श्याम सिंह नागियान जिला पंचायत सदस्य भी रहे और कांग्रेस के मजबूत स्तंभ भी माने जाते थे। जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने शिक्षा के मंदिर की ज्योति सदैव जगमगाने के लिए उन्होंने रुड़की सिविल लाइंस के अपने आवास को छोड़कर स्कॉलर एकेडमी को ही अपना आशियाना बना लिया था।

देश, पाँपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स? जीएसटी प्रणाली से सभी परेशान

सनत कुमार जैन

जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में एकीकृत कराधान प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस टैक्स के लागू होने के बाद अन्य सभी टैक्स खत्म हो जाने चाहिए थे। जीएसटी का उद्देश्य भारत की कराधान प्रक्रिया को सरल बनाना था। जब से जीएसटी लागू हुआ है। अभी तक जीएसटी कानून में हजारों संशोधन हो चुके हैं। जीएसटी कानून में एक ही उत्पाद पर अलग-अलग टैक्स की दरें हैं। सीए कारोबारी, वकील उपभोक्ता सभी जीएसटी कानून से परेशान हो चुके हैं। मुकदमों की बाढ़ आ चुकी है। सरकार हर लेनदेन को जीएसटी के दायरे में लेकर आई है। 65 फीसदी जीएसटी की वसूली गरीब और मध्यम वर्ग से हो रही है। जीएसटी में टैक्स की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। हाल ही में पाँपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी की दरों के निर्णय ने एक बार फिर कर प्रणाली की जटिलताओं को उजागर किया है। 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में गरीबों के पाँपकॉर्न पर लगाए गए टैक्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया में वीडियो रियल और व्यंग्य के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। अब

सॉल्टेड पाँपकॉर्न पर 5 फीसदी पैकड पाँपकॉर्न पर 12 फीसदी, और कैरेमल पाँपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। जीएसटी के इस वर्गीकरण ने आम जनता को भी उलझन में डाला है। कराधान प्रणाली को लेकर अब आम से खास तक सभी हैरान और परेशान हैं, जीएसटी को सरल और तर्कसंगत प्रणाली के रूप में केंद्र सरकार ने पेश किया था। बड़े-बड़े सब्जिबाग उपभोक्ताओं को दिखाए गए थे। एक कर प्रणाली से महंगाई कम होगी। टैक्स की चोरी रुकेगी। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया ने इसे जटिल बना दिया है। भारत में लागू जीएसटी कानून दुनिया का सबसे जटिल कानून है। जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है। पाँपकॉर्न जैसे उत्पाद पर तीन अलग-अलग टैक्स, इसका जीता-जागता उदाहरण है। जीएसटी कानून में इस तरह के वर्गीकरण से उपभोक्ता को भ्रमित करता है। जीएसटी के नाम पर उपभोक्ता से लूट की जा रही है। कारोबारियों और कर अधिकारियों के लिए भी जीएसटी के कानून हैरान और परेशान करने वाले हैं सरकारी अधिकारियों ने इसे लूट और रिश्वत के लिए मुफ़ीद साबित हो रहा है। जीएसटी कानून की विसंगतियों के कारण न्यायालय

में मुकदमे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पाँपकॉर्न पर लगाए गए टैक्स के बाद सोशल मीडिया में व्यंग्य और मीम्स की बाढ़ आ गई है। सारी दुनिया में भारत का पापकॉर्न ट्रेंड कर रहा है। जनता सरकार के इस फैसले से काफी नाराज है। गरीबों और मध्यम वर्ग की दैनिक उपयोग की जरूरतों पर जमीनी हकीकत से विपरीत भारी टैक्स लगाया जा रहा है। मेटू बड़ा और पानी कफ़न और अन्य चीजों पर जो टैक्स लगा है। इस पर जनता ने सरकार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जनता का विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे वैसे ही गम्बर सिंह टैक्स नहीं कहती है। सरकार ने भी अब यह साबित करना शुरू कर दिया है कि यह वास्तव में गम्बर सिंह टैक्स ही है। जीएसटी कानून में सरकार ने हजारों संशोधन कर दिए हैं। एक ही उत्पाद पर अलग-अलग टैक्स दरों की वसूली की जा रही है। प्रणाली में वर्गीकरण की खामियों से कर चोरी जैसे गंभीर मुद्दे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग से भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 2.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी दर्ज हुई है। उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर

ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है। जीएसटी प्रणाली को जनता के लिए सरल और व्यापारियों के लिए सुगम बनाने का सपना दिखाया गया था। उत्पादों पर टैक्स दर तय करते समय जटिलता खत्म करनी होगी एक देश, एक टैक्स के वादे को वास्तविकता में बदलने के लिए अन्य टैक्स खत्म करने होंगे सरकार जीएसटी के वर्तमान कानून के सुधार पर विचार करे। पाँपकॉर्न टैक्स का यह विवाद केवल टैक्स का मुद्दा नहीं है। यह जनता और सरकार के बीच इस टैक्स को लेकर लगातार असमंजस और विरोध बढ़ता चला जा रहा है। जीएसटी के कारण हर चीज महंगी हो गई है। हर स्तर पर इसमें बार-बार टैक्स लग रहा है। एक ही वस्तु पर कई तरह के टैक्स दर होने से उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। कराधान का उद्देश्य राजस्व जुटाने के साथ-साथ जनता को राहत देना भी है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा, उसकी नीतियां जनता के हितों के अनुरूप हों। सरकार को गरीब एवं मध्यमवर्ग की जरूरतों को समझना होगा। जिस तरह से सरकार जीएसटी में कर वसूल कर रही है। उसको लेकर अब जनता के मन में गुस्सा देखने को मिलने लगा है। सरकार को समय रहते इसे समझना होगा।

बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल-शिक्षक व अभिभावक पढ़ाई में मार्गदर्शन करेंगे

किशन सनमुखदास भावनारों

वैश्विक स्तर पर न केवल मानवीय जीव के लिए शिक्षा ग्रहण करना उसकी सफलता की कुंजी है बल्कि उसने संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा माना जाएगा जैसे भारत को विजन 2047 में हर व्यक्ति के शिक्षित होने से इस विजन को एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा इसलिए ही केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा पर जोर दे रही हैं गुणवत्ता शिक्षा के लिए अनेक रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इसी दिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार दिनांक 21 दिसंबर 2024 को भारत के गजट में 16 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को प्रकाशित किया है, जिसमें अब नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अब 5 वीं व 8 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अब पास नहीं किया जाएगा। हालांकि दो माह के अंदर दूसरी परीक्षा ली जाएगी, परंतु अगर उसमें भी वह फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा परंतु निष्कासित नहीं किया जा सकता।

हालांकि 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद 16 राज्यों ने पहले से ही फेल नहीं करने की नीति को समाप्त कर दिया था, क्योंकि शिक्षा यह राज्य का विषय है परंतु अब केंद्र सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर फेल को फेल ही रहने देने की अधिसूचना जारी कर दी है। चूंकि बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल है शिक्षक व अभिभावक पढ़ाई में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा के स्तर में सुधारों की दिशा में बड़ा कदम, अब 5 वीं से 8 वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल विद्यार्थी फेल

ही रहेंगे।

साथियों बात अगर हम शनिवार दिनांक 21 दिसंबर 2024 को जारी केंद्रीय गजट में अधिसूचना की करें तो, अब पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षा में फेल होनेवाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया

जाएगा। सरकार ने निरुशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन किया है। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज, 21 दिसंबर 2024 को बड़ा फैसला करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब कक्षा 5 वीं और 8 वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र दोबारा फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बच्चे को रोके रखने के दौरान शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो अभिभावक का भी मार्गदर्शन करेंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 हजार से अधिक स्कूलों पर लागू होगा। वहीं मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। पहले ही 16 राज्यों और दिल्ली सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को पहले ही खत्म कर दिया है। साथियों बात

अगर हम अधिसूचना को समझने की करें तो, एक गजट अधिसूचना के अनुसार, नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद, यदि कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे दो महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनरुपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा अधिसूचना में कहा गया है, यदि पुनरुपरीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नीति को जारी रखने का फैसला किया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद यदि कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे परिणाम की घोषणा की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला छात्र पदोन्नति (अगली कक्षा में जाने की अर्हता) के मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे पांचवीं या आठवीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित

नहीं किया जाएगा। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल होते हैं, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8 वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। बता दें 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के वजह से स्टूडेंट्स के सीखने का स्तर गिर रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करने के लिए टीचर्स के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। ज्यादातर मामलों में स्टूडेंट्स का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता था। देशभर में 10 पैसेट से भी कम स्कूलों में पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स और इंफ्रस्ट्रक्चर पाया गया। पॉलिसी में मुख्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस किया गया जबकि बेसिक शिक्षा का स्तर गिरता रहा। इससे स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो गए क्योंकि अब उन्हें फेल होने का डर नहीं था। 2016 की एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार क्लास 5 वीं के 48 पैसेट से कम स्टूडेंट्स ही दूसरी क्लास का सिलेबस पढ़ पाते हैं। ग्रामीण स्कूलों में आठवीं क्लास के सिर्फ 43 पैसेट स्टूडेंट्स ही सिम्पल डिवाइजन कर सकते हैं। 5 वीं क्लास में चार में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही अंग्रेजी का वाक्य पढ़ सकता है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रारंभिक शिक्षा पर आर्टिकल 16 के इस असर को लेकर चिंता जताई थी। शिक्षा पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी और सीएबीसी के तहत बनाई गई वासुदेव देवनानी कमेटी ने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने की सिफारिश की थी नो

डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा थी। ये सरकार की पहल थी जिससे भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जा सके ताकि वो स्कूल आते रहें। फेल होने से स्टूडेंट्स के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। साथ ही फेल होने से बच्चे शर्म भी महसूस करते हैं जिससे पढ़ाई में वो पिछड़ सकते हैं। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई जिसमें 8 वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता। 2018 में लोकसभा में बिल पास हुआ था जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया था। इसमें स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात थी। इसके अनुसार 5 वीं और 8 वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एग्जाम्स की मांग की गई थी। इसी के साथ फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए दो महीने के अंदर री-एग्जाम कराने की भी बात थी। 2019 में ये बिल राज्य सभा में पास हुआ। इसके बाद राज्य सरकारों को ये हक था कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या लागू रख सकते हैं। यानी राज्य सरकार ये फैसला ले सकती थीं कि 5 वीं और 8 वीं में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट किया जाए या क्लास रिपीट करवाई जाए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा के स्तर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम-अब 5 वीं से 8 वीं की वार्षिक परीक्षा मंक फेल विद्यार्थी फेल ही रहेंगे। लंबे बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल-शिक्षक व अभिभावक पढ़ाई में मार्गदर्शन करेंगे विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर 2 माह के भीतर दूसरा मौका मिलेगा, फिर भी फेल हुआ तो रोक दिया जाएगा पर निष्काशन नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार-चुनावी रणनीति और विकास के अवसर

सत्यप्रकाश दुबे

छत्तीसगढ़, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता और आदिवासी विरासत के लिए जाना जाता है, वर्तमान में अपने राजनीतिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आगामी नगरीय और पंचायत चुनाव तथा प्रदेश में चल रही विकासोन्मुखी योजनाओं की दिशा में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल विस्तार के विचार में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह प्रक्रिया न केवल राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक संरचना पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। राज्य के मंत्रिमंडल में विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार राज्य में मंत्रिमंडल के लिए अधिकतम 14 सदस्य शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में 11 मंत्री हैं, जिसका अर्थ है कि तीन और मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को समझना आवश्यक है। सबसे पहले, 2024 के अंत में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव तथा त्रि-स्तरीय

पंचायत चुनाव के लिए तैयार होना पहली प्राथमिकता है। आगामी चुनावों से पहले सभी क्षेत्रों में विकास योजनाओं को बढ़ावा देना और जनता के साथ संवाद को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा, वर्तमान मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसे संतुलित करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों और जातीय समूहों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभागों के हिसाब से हो। बिलासपुर संभाग के नेताओं में अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमर अग्रवाल एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने पूर्व में वित्त और नगरीय प्रशासन जैसे विभाग संभाल चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। धरमलाल कौशिक, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठनात्मक मजबूती के साथ क्षेत्रीय पकड़ भी रखते हैं। इन दोनों नेताओं की विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग मंत्रिमंडल के विस्तार में किया जा सकता है। बस्तर संभाग, जो आदिवासी बहुल है और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना

जाता है, वहां से किरण देव और विक्रम उसेंडी जैसे नेता संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। किरण देव एक युवा आदिवासी नेता हैं जिनकी राजनीति में मजबूत पकड़ है और वे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। विक्रम उसेंडी राज्यसभा सदस्य और आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं जो इस क्षेत्र को एक सशक्त प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से सरकार इस वर्ग का विश्वास जीत सकती है, जो कि चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रायपुर संभाग से राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और सुनील सोनी जैसे नेताओं का नाम लिया जा रहा है। राजेश मूणत एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने रायपुर में प्रभावशाली जनाधार बनाया है। अजय चंद्राकर, जिनका प्रशासनिक और संगठनात्मक कौशल उन्हें एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है, वे सरकार को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सुनील सोनी, जो एक उभरते नेता हैं और युवाओं तथा शहरी वर्ग में लोकप्रियता रखते हैं, वे भी मंत्रिमंडल में संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं। सरगुजा संभाग और अन्य आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग राज्य की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा

रखते हैं, और इन वर्गों का समर्थन सुनिश्चित करना आगामी चुनावों के लिए आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों से मंत्रियों का चयन कर, सरकार न केवल इस समुदाय का समर्थन प्राप्त कर सकती है बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित कर सकती है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना भी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। महिला विधायकों को शामिल कर सरकार महिला मतदाताओं और युवा वर्ग के बीच अपनी छवि को बेहतर बना सकती है। यह कदम न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो सकता है बल्कि इससे सरकार की सामाजिक और राजनीतिक छवि भी मजबूत हो सकती है। सत्ताधारी दल के भीतर विभिन्न गुट अपने-अपने उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए दबाव बना सकते हैं। यह भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि इससे आंतरिक राजनीति और संतुलन प्रभावित हो सकता है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, खासकर अगर किसी क्षेत्र या वर्ग को नजर अंदाज किया गया। विपक्ष सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विभिन्न मुद्दे उठा सकता है, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन, जातीय पक्षपात, या महिला प्रतिनिधित्व की कमी। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देना भी सरकार के

लिए एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ के जमानस की विविधता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर क्षेत्र और हर वर्ग की आवाज मंत्रिमंडल में सुनाई दे। इससे न केवल सरकार की छवि में सुधार होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। नए मंत्रियों की नियुक्ति के बाद, सरकार को विकास योजनाओं को गति देना और प्रशासनिक ढांचे को और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह कदम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और भी अधिक मजबूत बना सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े कुछ प्रमुख पहलू हैं जिन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले, क्षेत्रीय संतुलन एक महत्वपूर्ण कारक है। छत्तीसगढ़ को पांच प्रमुख संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजाकृम विभाजित किया गया है। वर्तमान मंत्रिमंडल में कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम है, जिसे संतुलित करना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी क्षेत्रों के लोगों को बराबर महत्व और अवसर मिलें। इससे सरकार को एकीकृत और संतुलित छवि प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सरकार इन वर्गों का विश्वास जीत सकती है।

मिलिट्री हॉस्पिटल, में आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह

संवाददाता

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आर्मी हॉस्पिटल (आर. आर. हॉस्पिटल) दिल्ली एवं मिलिट्री हॉस्पिटल, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व सैनिकों एवं परिवारजनों हेतु आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

आज यहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आर्मी हॉस्पिटल (आर. आर. हॉस्पिटल) दिल्ली एवं मिलिट्री हॉस्पिटल, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व सैनिकों एवं परिवारजनों हेतु आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जांच हेतु पहुंचे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से भी मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने



सैन्य अधिकारियों से मुलाकात उनसे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी कैंप लगाए जाने का सुझाव भी दिया। ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अधिक लाभ मिल सके। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं। यह शिविर 24 से 27 दिसम्बर तक सैन्य

अस्पताल में चलेगा। जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अपनी तरह का पहला निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन भी किया जाएगा। यह शिविर ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा और उनकी विशेषज्ञ टीम अत्याधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी को अत्याधुनिक उपकरणों और आयातित इंट्राओकुलर

लेंस के साथ कार्य करेंगे। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली की एक प्रतिष्ठित टीम के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करना है। शिविर के दौरान मोतियाबिंद की जांच और उसके बाद योग्य मामलों के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएँ की जाएँगी। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली के अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा उपकरणों के साथ मोतियाबिंद की सर्जरी भी जाएगी, जिसमें आयातित उन्नत प्रीमियम इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण भी शामिल है, जिससे उच्चतम गुणवत्ता वाला उपचार सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर कमाण्डेंट मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून ब्रिगेडियर परीक्षित सिंह, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा सहित अन्य सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संगठन की कार्यकारिणी का गठन नए वर्ष में होगा

ऋषिकेश। राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन नए वर्ष में किया जायेगा। आज यहां राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संगठन के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन संगठन कार्यालय में किया गया। बैठक में अभिकर्ताओं की समस्याओं, संगठन का लेखा-जोखा एवं नई कार्यकारिणी के संबंध में वार्तालाप की गई। बैठक में अभिकर्ताओं की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया और निस्तारण भी किया गया। बैठक में कोषाध्यक्ष अजय ब्रेजा ने संगठन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर के समाज सेवियों को समय-समय पर संगठन की ओर से सम्मानित किया जाएगा और उनके विचारों को अमल में लाया जाएगा। बैठक में गीता सचदेवा, गोल्डी ब्रेजा, रीना ढींगरा, मंजू शर्मा, रेखा शुक्ला, शशि मिश्रा, संगीता गुप्ता, नंदकिशोर अग्रवाल, शिखा ब्रेजा, रमा गौतम, अनीता रैना, रविंद्र प्रकाश भारद्वाज, हंसराज मंदोलिया, शिवकुमार गौतम, योगेश ब्रेजा, राजेंद्र रैना व तमाम सदस्य उपस्थित थे।

उत्तराखंड जवाहर नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड जवाहर नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन के सम्मेलन में पूर्व में किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी। आज यहां उत्तराखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों का देहरादून में सम्मेलन का आयोजित किया गया। सम्मेलन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। साथ ही पूर्व में किये गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे के साल भर के किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई।

गौरतलब है कि पूरे देश में हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित होता है, इस तरह देश में वर्तमान में देश में विद्यालय हैं। यह विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय होते हैं, जिसमें छात्र पूर्व रूप से छात्रवृत्ति के तहत पढ़ाई करते हैं। इन विद्यालयों पूरी सुविधाएँ केंद्र सरकार से

वित्त पोषित होती हैं। इन विद्यालयों के पढ़ाई किये छात्र आज देश में हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अन्य राज्यों की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी



भूतपूर्व छात्रों के एसोसिएशन को संस्था के रूप में रजिस्टर करने और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चयन हेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एसोसिएशन संस्था का नाम सर्व सहमति से उत्तराखंड जवाहर नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन रखा गया। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें 2025 में होने वाली गतिविधियों

और संगठन के भविष्य को लेकर विचार-विमर्श किया गया। संस्था के प्रस्तावित कार्यों में जवाहर नवोदय से पास होने के उपरांत उच्च शिक्षा हेतु

जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, नवोदय में अध्ययनरत छात्रों को करियर गाइडेंस देना, नवोदय से पढ़े बच्चों को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा संचालित व्यवसायों आदि में रोजगार प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी गतिविधियां आयोजित करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना आदि शामिल हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यदीप शाह, उपाध्यक्ष रमेश सिंह रावत, हरिश चौहान, सचिव अचला असवाल, विकास रिन्वी, कोषाध्यक्ष अरुण सैनी, मीडिया प्रभारी विक्रम ठाकुर, सोशल मीडिया प्रभारी रश्मि रावत, आकाश जोशी निर्वाचित हुए।

सत्ता और पद के नशे से लड़खड़ाता सिस्टम

जब भी समाज घातक घटनाओं को नजरअंदाज करता है और उन पर कोई स्टैंड नहीं लेता तो वे नज़ीर बन जाती हैं। अठारह साल पहले स्व जुगलकिशोर बागरी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक बाबू का कालर पकड़ लिया था वे तब जल संसाधन मंत्री थे। उसी काल में एक और मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी एक डाक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। घटनायें तो भुला दी गईं किंतु विकृति बढ़ती गई है। देश आज जिस राह पर है वह निश्चित ही चौंकाने वाला है। प्रतिक्रियायें हिंसक और उन्मादी होती जा रही हैं। सीमायें अपने आप टूट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। पूर्व में हुई तीन घटनाओं की तरह एक ही सप्ताह में फिर से वैसी ही नई घटनायें सामने आ गई हैं। जो झकझोरती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने अपने सार्वजनिक भाषण में अल्पसंख्यकों को कठमुल्ला कहते हुए उन्हें देश के लिये खतरनाक बताया है। वे कथित रूप से बहुसंख्यकों के अनुसार देश चलाने की बात भी कहते हैं। उनके विरुद्ध महाअभियोग लाने की बात हो रही है। यह रेडिकलाइजेशन (कट्टरता) की नई नज़ीर है। इससे भी खतरनाक घटना गाजियाबाद के जिला जज द्वारा छोटी सी बात पर वकीलों से हुए वाद विवाद में जिला न्यायाधीश और वकीलों के बीच में कथित झूमा झटकी की है, जहां पुलिस द्वारा वकीलों की जबरदस्त पिटाई के बाद वकीलों द्वारा अदालत के बाहर पुलिस चौकी में आग लगा देने की है। यह दोनों घटनायें न्यायपालिका के आचरण पर रोशनी डालती हैं। अगर न्यायाधीश इतने ही प्रतिक्रियावादी हो जायेंगे तब निष्पक्ष न्याय की परिकल्पना ही व्यर्थ है। कल तक तो न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी थी लेकिन आज तो पट्टी हटा दी गई है, तब जजों और वकीलों का यह कथित व्यवहार स्पष्ट संकेत है कि प्रतिक्रिया का उत्तेजक जहर पूरे कुएं में घुल चुका है। एक राष्ट्रीय दल के बड़े नेता के विरुद्ध विदिशा में शर्मनाक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी भतीजी ने ही उस पर यौन शोषण और रेप के आरोप लगाये हैं। हालांकि भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है किंतु यह वासनागत उन्माद की पराकाष्ठा है जिसमें रिश्ते तार तार हो गये हैं। पारिवारिकता के रिश्तों को भी अब संशय की नजर से देखा जायेगा।

बालों को धोते हुए लोग करते हैं ये 5 गलतियां, हो सकता है बड़ा नुकसान

गर्मियों के मौसम में लोग अपने बालों को लेकर परेशान हो जाते हैं। इस समय कई लोग अपने बालों के झड़ने, डैंड्रफ की समस्या, बालों का रंग उड़ जाने या फिर उम्र से पहले सफेद पड़ जाने से काफी परेशान रहते हैं। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मौजूद कई तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बाजार से खरीदी हुई महंगी दवाई या फिर तेल भी बालों पर कोई असर नहीं कर पाते।

क्या आप जानते हैं कि बालों के खराब होने का कारण या फिर बालों के झड़ने के पीछे आपकी ही की हुई कुछ सामान्य गलतियां होती हैं। आपकी छोटी-छोटी गलतियां या फिर लापरवाही ही आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है। आइए आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में

जो आपके बालों के खराब होने या फिर उनके झड़ने के पीछे के बड़ा कारण हो सकते हैं।

गर्म पानी से न धोएं बाल

आप अपने बालों को धोने के लिए ठंडे पानी या फिर गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से धोने की कोशिश करें ताकि आपके बालों में किसी तरह का कोई नुकसान न हो। वहीं, अगर आप गर्म पानी से बालों को धोएंगे तो आपके बाल जड़ों से कमजोर हो सकते हैं। गर्म पानी बालों को खराब करने का काम करता है।

शैम्पू का सही तरीके से करें इस्तेमाल

लोग अक्सर बाल धोते समय शैम्पू को बिना पानी के ही सीधा अपने बालों में

लगा लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से आपके बालों को काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। अगर आप



शैम्पू को पानी में मिलाकर लगाएंगे तो आपके बालों को कम नुकसान पहुंचेगा। आप कोशिश करें की जब भी आप शैम्पू करें तो आप पानी में शैम्पू को मिलाकर

फिर बालों में लगाएं।

बालों पर ज्यादा जोर न दें

कई बार हम अपने बालों पर ब्रशिंग करते समय काफी ज्यादा ताकत लगा देते हैं जो कि हमारे बालों को कमजोर करके तोड़ने का काम करता है। जब लड़कियां अपने बालों में बैंड लगाती है तो वो काफी टाइट हो जाते हैं। इस कारण बाल कमजोर होते हैं और बालों के टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है।

तौलिए या टावल का रखें ख्याल लोग नहाने के बाद एक ही तौलिए से शरीर को भी सूखाते हैं और उसी से बालों

को भी सुखाते हैं, जो कि आपके बालों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आप बालों को तौलिए से सुखाना चाहते हैं तो आप बालों के लिए एक अलग टावल रखें। इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं की बाल अपने आप ही सूख जाएं, जिससे आपके बालों में किसी तरह का नुकसान न हो। जितना हो सके ड्रायर का भी कम उपयोग करें।

सही तकिया चुनें

हम जब सोते समय अपने सिर के नीचे तकिया लगाते हैं वो भी हमारे बालों के लिए एक नुकसानदायक है। हम सामान्य सूती तकिया का प्रयोग करते हैं जो हमारे बालों को तोड़ता है और खराब करने का काम करता है। हमें सिर के नीचे नरम तकिया रखना चाहिए जो हमारे बालों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए।

एक नजर

सड़क किनारे परोस रहा था शराब, गिरफ्तार

अल्मोड़ा (हमारे संवाददाता)। सड़क किनारे शराबियों को शराब परोस रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके कब्जे से 60 पच्चे देशी



शराब बरामद की गयी है। बीती रात थाना द्वारा हाट पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सड़क किनारे शराबियों को शराब उपलब्ध करा रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बताया गये स्थान दूनागिरी रोड पर चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को वहां एक व्यक्ति लोगों को शराब परोसता हुआ दिखायी दिया। पुलिस ने जब उसे पकड़ कर तलाशी ली तो उसके पास से 60 पच्चे देशी शराब बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम जीवन सिंह पुत्र खीम सिंह निवासी ग्राम नौवाड़ा तहसील द्वाराहाट बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

चोरी की नौ मोटरसाइकिलों के साथ तीन गिरफ्तार

देहरादून (संवाददाता)। पुलिस ने चोरी की नौ मोटरसाइकिलों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी हरबर्टपुर देहरादून द्वारा कोतवाली विकासनगर पर प्रार्थना पत्र दिया कि उनके घर के बाहर से उनकी मोटर साइकिल सुपर स्लेंडर चोरी कर ली है। सोहिल पुत्र अब्दुल वहीद निवासी जमुनीपुर विकास नगर ने कोतवाली विकास नगर पर प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है। वाहन चोरी की घटनाओं की गम्भीरता के



दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के खुलासे तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास आने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन करते हुए संदिग्धों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी। सीसीटीवी फुटेजों से प्राप्त संदिग्धों के हलिये के साथ ही सुरागरी पतारसी करते हुए पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में जेल में गये लोगों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप चैकिंग के दौरान रात्रि हरबर्टपुर कुल्हाल रोड पर शक्ति नहर पुल के पास से तीन संदिग्धों को एक मोटर साइकिल पर जाते समय रोक कर वाहन के कागज मांगे गये तो वो कोई भी कागज नहीं दिखा पाये पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त बाइक को हरबर्टपुर क्षेत्र से चोरी किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों ने अपना नाम आमिर पुत्र इसरार, शाकीर रावत पुत्र रहमत अली तथा अनस पुत्र इस्राक सभी निवासी हरियाणा बताया गया। संख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही पर पर कुल्हाल पुल से करीब 02 किलोमीटर आगे धौला तप्पड़ की ओर जंगल में बने खंडहर से चोरी करके छिपाई गयी 08 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। बरामद बाइकों में से 02 बाइकें थाना विकास नगर से चोरी की गई हैं, शेष अन्य बरामद बाइकों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। आरोपी नशा करने के आदी हैं तथा अपनी नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उनके द्वारा उक्त वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आरोपियों द्वारा पहचान छिपाने तथा पकड़े जाने के डर से चोरी की गयी सभी मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेटें निकालकर फेंक दी गयी थी। जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मंदिर की दीवार से सटे मकान में कर दी गोकशी, हंगामा

आरोपित फरार, घटना को लेकर तनाव पुलिस बल तैनात

हरिद्वार (हमारे संवाददाता)। मंदिर की दीवार से सटे एक मकान में कुछ लोगों ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर जमकर हंगामा हुआ। जबकि आरोपित फरार हो गया। घटना को लेकर क्षेत्र



में तनाव है और मौके पर पुलिस बल मौजूद है। जानकारी के अनुसार रुड़की से सटे जोरासी गांव में बीती रात एक मंदिर की दीवार से सटे एक मकान में कुछ लोगो ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया। यह मकान मुस्लिम परिवार का है। लोगो को जब इसका पता चला तो जमकर हंगामा किया। जबकि आरोपित वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने से पुलिस के हाथपाव फूल गए। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मौके से गोमांस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में जम्मू निवासी जोरसी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना को लेकर अभी भी तनाव है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

गाडी की साईड लगने पर मारपीट कर किया घायल

संवाददाता

देहरादून। गाडी की साईड लगने पर मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खोदरी माजरी सिरमौर हिमाचल प्रदेश निवासी रघुवीर सिंह व विक्की ठाकुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह जुड़ो में अपनी दुकान चलाते हैं, जिसके लिए वह दोनों सुबह जाते हैं और शाम को दुकान बन्द करके अपने गांव खोदरी माजरी, तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में आते-जाते हैं।

जब वह अपनी दुकान बन्द करके जुड़ो से वापस आ रहे थे तो डुमेट गांव में रात्रि करीब पौने नौ बजे पुल के पास सफेद रंग की महिन्द्रा बुलरो गाडी खडी थी, जिसमें केंदार सिंह व सन्तराम नामक भारी मात्रा में विदेशी/ इम्पोर्टेड शराब का जखीरा बरामद

बरामद शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपये

देहरादून (संवाददाता)। पुलिस ने एक फ्लेट पर छापा मार वहां से शराब का जखीरा बरामद किया। पकडी गयी शराब की कीमत 25 लाख रुपये आंकी जा रही है। पुलिस ने फ्लेट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी आदेशों के अनुपालन में जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे अभियुक्तों के चिन्हकरण/धरपकड हेतु लगातार सत्यापन/चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर थाना राजपुर पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्रान्तर्गत प्लॉट नंबर 5 शिप्रा विहार, कैनाल रोड उक्त फ्लैट में बनाये गये अवैध शराब के गोदाम पर छापा मारते हुए वहां से 16 पेटी (कुल 181 बोतल) अवैध इम्पोर्टेड शराब बरामद की। जिसमें से कुछ शराब की बोतलें हरियाणा मार्का भी थी। पुलिस द्वारा फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सिम कार्ड बंद होने का झांसा देकर ठगे पौने चार लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। सिम कार्ड बंद होने का झांसा देकर पौने चार लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर आरकेडिया निवासी देवेन्द्र सिंह ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसको एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को उसके मोबाइल सेवा प्रदाता जिओ का प्रतिनिधि बताया, कॉल करने वाले ने उसका नाम और अन्य संपर्क विवरण सत्यापित किया, जिससे उसको विश्वास हुआ कि वह व्यक्ति वास्तविक है। उसने

व्यक्ति बैठे हुए थे तथा गाडी का दरवाजा भी खुला था, वह मोटर साईकिल को दरवाजे से बचाते हुए साईड से निकल रहे थे तभी अचानक एक कुत्ता सामने आ गया, जिस कारण मामूली साईड लग गई, जिसके बाद केंदार सिंह व सन्तराम ने गाडी से उतरकर उनके साथ गाली-गलौच की, जिसे सुनकर वह वहीं रूक गये तभी केंदार सिंह व सन्तराम ने वहीं होटल से 6-7 लोगो को बुलाया और उन सभी ने मिलकर उनके ऊपर तेज धारदार हथियार, खुखरी व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद वो सभी उनको मारते रहे। जिसमें उनके पूरे शरीर में गम्भीर चोटे आईं, और विक्की ठाकुर का एक कान तेज धारदार हथियार से कट गया, तथा रघुवीर जबडा भी टूट गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

दो साल से फरार वारंटी पंजाब से गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चमोली। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें में दो साल से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी फरार अपराधियों की धर पकड़ करने संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना गोविंदघाट पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पुलिस ने पिछले दो वर्षों से फरार



चल रहे नेपाली मूल के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी मित्रागिरी पुत्र शालिग्राम निवासी ग्राम खवाड थाना व जिला प्यूठान नेपाल थाना गोविंदघाट में दर्ज आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें में आरोपी था। जमानत मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह पंजाब के पटियाला शहर में छिपा हुआ है। इसके बाद, गोविंदघाट पुलिस की एक टीम को पटियाला भेजा गया। पुलिस ने बीती शाम साइ मार्केट, पटियाला से मित्रागिरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद, मित्रागिरी को चमोली लाया गया और अदालत में पेश किया गया है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक कांति कुमार

संपादक पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार: वी के अरोड़ा, एडवोकेट

बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।